



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 142]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 15, 2012/ज्येष्ठ 25, 1934

No. 142]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 15, 2012/JYAISTHA 25, 1934

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2012

(निर्णायक समीक्षा)

विषय : यूरोपियन यूनियन, दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित एसीटोन के आयातों के संबंध में अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा।

सं. 15/1/2012-डीजीएडी.—यतः समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात् अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियम, 1995 (जिसे एतदपश्चात् पाटनरोधी नियमावली कहा गया है) के अनुसार यूरोपियन यूनियन, ताईवान, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित एसीटोन (जिसे एतदपश्चात् सम्बद्ध वस्तु कहा गया है) के आयात पर दिनांक 4 जनवरी, 2008 की अधिसूचना सं. 14/4/2006-डी जी ए डी के तहत निर्णायक पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित करने की मूलतः संस्तुति की गई थी और यतः केन्द्रीय सरकार ने दिनांक 11 मार्च, 2008 की अपनी अधिसूचना सं. 33/2008-सीमा शुल्क जारी की थी।

2. यतः, मै. हिन्दुस्तान आर्गनिक कैमिकल्स लिमिटेड (एच ओ सी एल) ने अधिनियम और पाटनरोधी नियमावली के अनुरूप निर्दिष्ट प्राधिकारी (प्राधिकारी) के समक्ष, यूरोपियन यूनियन, सिंगापुर, ताईवान, दक्षिणी अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित एसीटोन का पाटन जारी रहने का आरोप लगाते हुए एक आवेदन-पत्र दायर किया है और पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने और उसे जारी रखने का अनुरोध किया है।

3. और यतः, इसी बीच निर्दिष्ट प्राधिकारी ने सम्बद्ध वस्तु के ताईवान से आयात के विरुद्ध मध्यावधि समीक्षा निष्कर्ष सम्पन्न कर लिया और दिनांक 10 अप्रैल, 2012 की अधिसूचना के तहत ताईवान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सम्बद्ध वस्तु से पाटनरोधी शुल्क वापस लेने की संस्तुति कर दी। अतः आवेदक ने एक संशोधित आवेदन दायर किया जिसमें यूरोपियन यूनियन, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका (जिसे एतदपश्चात सम्बद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित एसीटोन का पाटन जारी रहने का आरोप लगाया है और पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने और उसे जारी रखने का अनुरोध किया है।

घरेलू उद्योग

4. यह आवेदन मै0 हिन्दुस्तान आर्गनिक कैमिकल्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार, आवेदक का पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) और 5(3) (क) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से पाटनरोधी जांच के लिए मामला दायर करने का आधार बनता है।

विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

5. मूल जांच में शामिल उत्पाद एसीटोन था। यह निर्णायक समीक्षा होने के कारण मूल जांच में शामिल उत्पाद को इस जांच में भी शामिल किया जाता है।

6. एसीटोन एक कार्बनिक रसायन है जिसे डाइमिथायल कीटोन के रूप में भी जाना जाता है और इसका प्रयोग भारी मात्रा में फार्मास्युटिकल्स, कृषि रसायन, रंजक सामग्री, निश्चित विस्फोटकों और उसके सम्बद्ध रसायनों का विनिर्माण करने में किया जाता है। एसीटोन को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 29 के अन्तर्गत उपशीर्षक 29141100 के तहत वर्गीकृत किया गया है।

7. यह एकल ग्रेड में उत्पादित एक आधारभूत रसायन है। यह रंगीन तरल है जिसकी ईंथर की तरह खुशबू होती है। इसका प्रयोग विभिन्न कार्बनिक सिन्थेन्सिस में साल्वेंट या मध्यवर्ती के रूप में किया जाता है।

8. इसका प्रयोग भारी मात्रा में फार्मास्युटिकल्स, कृषि रसायन, रंजक सामग्री, कुछ निश्चित विस्फोटकों और उसके सम्बद्ध रसायनों का विनिर्माण करने में किया जाता है। एसीटोन का प्रयोग विशेष रूप से आइसोफोरोन, डायएसीटोन, अल्कोहल, मिथायल मेराक्रायलेट और

बिशफेनोल ए. का विनिर्माण करने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त, इसका प्रयोग कुछ रबड़ रसायनों अथवा आक्सी एसीथाइलीन सेल्यूलोज एसीटेट का विनिर्माण करने में भी किया जाता है।

9. घरेलू उद्योग भी समान गुणधर्म और विशेषताओं युक्त एसीटोन का उत्पादन करता है। विगत जांच में किसी हितबद्ध पक्षकार ने विचाराधीन उत्पाद अथवा समान वस्तु के मुद्दे पर कोई तर्क नहीं दिया है, इसलिए प्राधिकारी का विचार है कि घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित किया जा रहा उत्पाद पाटनरोधी नियमावली के अनुसार विचाराधीन उत्पाद के 'समान वस्तु' है।

शुरूआत

10. अतः, साक्ष्यों सहित विधिवत दायर आवेदन और पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 क(5) के अनुसार प्राधिकारी सम्बद्ध वस्तु के संबंध में प्रभावी शुल्क का अधिरोपण जारी रखने की जरूरत की समीक्षा करने और यह जांच करने के लिए क्या इस शुल्क को समाप्त कर देने से पाटन जारी रहेगा अथवा उसकी पुनरावृत्ति होगी और इससे घरेलू उद्योग को क्षति होगी, एतद्वारा एक निर्णायक समीक्षा जांच प्रारम्भ करते हैं।

शामिल देश

11. इस जांच में शामिल देश यूरोपियन यूनियन, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं।

जांच की अवधि

12. वर्तमान समीक्षा के उद्देश्य के लिए जांच की अवधि (पी ओ आई) 1 जनवरी, 2011 से 31 दिसम्बर, 2011 (12 माह) है। तथापि, क्षति विश्लेषण में वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 और जांच अवधि भी शामिल होगी। पाटन एवं क्षति की सम्भाव्यता का निर्धारण करने के लिए जांच अवधि से परे के आंकड़ों की जांच की जा सकती है।

प्रक्रिया

13. इस प्रक्रिया में दिनांक 4 जनवरी, 2008 (मूल जांच के अन्तिम निष्कर्ष) की अधिसूचना सं. 14/4/2006 - डी जी ए डी के सभी पहलू शामिल रहेंगे।

सूचना प्रस्तुत करना

14. सम्बद्ध देशों के ज्ञात निर्यातकों और सम्बद्ध देशों के भारत स्थित दूतावासों के जरिए उनकी सरकारों और इस उत्पाद से संबंधित भारत के ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं को निर्धारित स्वरूप एवं ढंग से संगत सूचना उपलब्ध कराने तथा अपने विचारों से प्राधिकारी को अधोलिखित पते पर अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है।

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
पाटनरोधी एवं सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य विभाग
कमरा सं. 243, उद्योग भवन
नई दिल्ली-110107

कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समयावधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित ढंग से जांच से संगत निवेदन कर सकता है।

समय-सीमा

15. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई हेतु किया गया कोई भी अनुरोध लिखित में भेजा जाना चाहिए जो प्राधिकारी के पास उपर्युक्त पते पर इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस (40) दिनों से अनधिक समय के भीतर पहुंच जाना चाहिए। यदि निर्धारित समयावधि के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण है तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमों के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

16. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे प्रस्तुत मामले में अपने हित (हित की प्रवृत्ति सहित) के बारे में सूचित करें और अपनी-अपनी प्रश्नावलियों के प्रत्युत्तर दायर करें तथा पाटनरोधी उपायों को जारी रखने अथवा नहीं जारी रखने की आवश्यकता के बारे में घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां इस जांच के शुरू होने की तारीख से चालीस (40) दिनों के अन्दर प्रस्तुत करें।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

17. प्रश्नावली के उत्तर/निवेदन के किसी भाग पर गोपनीयता का दावा किए जाने के मामले में इसे दो अलग-अलग भागों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए; (क) गोपनीयता के रूप में चिह्नित (शीर्षक, विषय सूची, पृष्ठों की संख्या आदि) और (ख) दूसरा भाग अगोपनीय के रूप में चिह्नित (शीर्षक, विषय सूची, पृष्ठों की संख्या आदि)। उपलब्ध कराई गई समस्त सूचना में प्रत्येक पृष्ठ पर ऊपर 'गोपनीय' अथवा "अगोपनीय" लिखा जाना चाहिए।

18. बिना चिह्न के उपलब्ध कराई गई सूचना अगोपनीय समझी जाएगी और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी किसी भी अगोपनीय सूचना के निरीक्षण की अनुमति प्रदान करने हेतु स्वतंत्र होंगे। गोपनीय पाठ और अगोपनीय पाठ दोनों की दो (2) पृथक प्रतियां प्रस्तुत की जानी चाहिए।

19. जिस सूचना के गोपनीय होने का दावा किया गया है उस सूचना के आपूर्तिकर्ता को उपलब्ध कराई गई सूचना के साथ कारणों का ब्यौरा प्रस्तुत करना अपेक्षित है कि ऐसी सूचना प्रकट क्यों नहीं की जा सकती है एवं/अथवा ऐसी सूचना का संक्षेप क्यों संभव नहीं है।

20. अगोपनीय पाठ गोपनीय पाठ की प्रतिकृति होना चाहिए और जिस सूचना के बारे में गोपनीयता का दावा किया गया हो उसे अधिमानतः सूचीबद्ध अथवा मिटाया/संक्षेपित किया जाना चाहिए। अगोपनीय सारांश में दिया गया ब्यौरा पर्याप्त होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय-वस्तु आसानी से समझी जा सके। तथापि अपवादात्मक परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार इंगित कर सकता है कि ऐसी सूचना संक्षेपण योग्य नहीं है और संक्षेपण संभव क्यों नहीं है, इसके कारणों का ब्यौरा निर्दिष्ट प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

21. प्रस्तुत की गई सूचना की जांच के उपरांत प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता हेतु अनुरोध आवश्यक नहीं है अथवा सूचना का आपूर्तिकर्ता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा सामान्य अथवा सारांश रूप में इसके प्रकटीकरण को प्राधिकृत करने का इच्छुक नहीं है तो वह ऐसी सूचना को नजरअंदाज कर सकते हैं।

22. सार्थक अगोपनीय पाठ के, बिना अथवा गोपनीयता के दावे के संबंध में दिए गए कारण के ब्यौरे के बिना प्रस्तुत की गई सूचना को निर्दिष्ट प्राधिकारी रिकॉर्ड में नहीं लेंगे। प्राधिकारी, प्रदत्त सूचना से संतुष्ट होने और गोपनीयता की आवश्यकता को स्वीकार कर लेने पर ऐसी

2162 GI/12-2

सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकार द्वारा विशिष्ट रूप से प्राधिकृत किए बिना किसी भी पक्षकार के समक्ष इसे प्रकट नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

23. नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतर वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

असहयोग

24. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उचित अवधि के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है अथवा जांच में बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

विजयलक्ष्मी जोशी, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 15th June, 2012

(Sunset Review)

Subject : Sunset review of Anti-Dumping Duty imposed in respect of imports of Acetone originating in or exported from European Union, South Africa, Singapore and USA.

No.15/1/2012-DGAD.—Whereas having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (herein after referred to as the AD Rules), the definitive anti-dumping duty was originally recommended vide notification No. 14/4/2006-DGAD dated 4th January, 2008 on import of Acetone (hereinafter referred to as the subject goods) originating in or exported from European Union, Taiwan, Singapore, South Africa and USA and whereas the Central Government issued its Notification 33/2008 - Customs, dated 11th March, 2008.

2. Whereas, M/s Hindustan Organic Chemicals Limited (HOCL) has filed an application in accordance with the Act and the AD Rules before the Designated Authority (Authority) alleging continued dumping of Acetone originating in or exported from European Union, Singapore, Taiwan, South Africa and USA and requested for review and continuation of the anti-dumping duties.

3. And whereas, the Designated Authority, in the meantime, concluded midterm review investigation against imports of subject goods from Taiwan and has vide Notification dated 10th April, 2012 recommended withdrawal of anti dumping duty from subject goods originating in or

exported from Taiwan. The applicant, therefore, filed a revised application, alleging continued dumping of Acetone originating in or exported from European Union, Singapore, South Africa and USA (hereinafter referred to as subject countries) and has requested for review and continuation of the anti-dumping duties.

Domestic industry

4. The application has been filed by M/s Hindustan Organic Chemicals Limited. As per the evidence available applicant has the standing to file the case for the anti dumping investigation on behalf of the domestic industry as per Rule 2(b) and 5(3) (a) of Anti dumping Rules.

Product under consideration and Like Article

5. The product involved in the original investigation was 'Acetone'. This being a Sunset review, therefore, the investigation covers the product covered in the original investigation.

6. Acetone is organic chemical also known as Dimethyl Ketone and used in the manufacture of bulk pharmaceuticals, agro chemicals, dye stuffs, certain explosives and downstream chemicals. Acetone is classified under Chapter 29 of Custom Tariff Act under the sub-heading 29141100.

7. It is a basic organic chemical produced in single grade. It is a colourless liquid with an agreeable ether-like odour. It is used in numerous organic synthesis either as solvent or as an intermediate.

8. It is used in manufacture of bulk pharmaceuticals, agro-chemicals, dyestuffs, certain explosives and downstream chemicals. Acetone is specifically used in manufacture of Isophorone, Diacetone, Alcohol, Methyl Methacrylate and Bishphenol A. Besides this, it is used in manufacture of certain rubber chemicals or Oxy Acethylene Cellulose Acetate.

9. The domestic industry also produces Acetone having similar characteristics and specifications. No argument has been extended, by any interested party in the previous investigation, on the issue of product under consideration or like article and therefore, the Authority considers that the product being manufactured by the domestic industry is 'like article' to the product under consideration as per the AD Rules.

Initiation:

10. Thus, in view of the duly substantiated application filed and in accordance with Section 9 A (5) of the Act, read with Rule 23 of the AD Rules, the Authority hereby initiates a Sunset review investigation, to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

Country involved:

11. The countries involved in this investigation are European Union, Singapore, South Africa and USA.

Period of Investigation:

12. The Period of Investigation (POI) for the purpose of the present review is 1st January 2011 to 31st December 2011 (12 months). However, injury analysis shall cover the years 2008-

2162 GI/12-3

09, 2009-10, 2010-11 & POI. The data beyond POI may also be examined to determine the likelihood of dumping and injury.

Procedure:

13. The review covers all aspects of Notification No. 14/4/2006-DGAD, dated 4th January, 2008 (final findings of the original investigation).

Submission of Information:

14. The known exporters in the subject countries, the government of the subject countries through its embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

**Government of India
Ministry of Commerce and Industry
Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties
Department of Commerce
Room No.243, Udyog Bhawan,
New Delhi-110107.**

Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

Time Limit:

15. Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the AD Rules.

16. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire's responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to continue or otherwise the AD measures within 40 days from the date of initiation of this investigation.

Submission of information on confidential basis.

17. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire's response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non-Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.

18. Information supplied without any mark shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies each of the confidential version and the non-confidential version must be submitted.

19. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

20. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out / summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible of summary; a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

21. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

22. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of public file:

23. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

24. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Governments as deemed fit.

VIJAYLAXMI JOSHI, Designated Authority